

राजस्थान बजट 2025-26

चर्चा में क्यों?

19 फरवरी, 2025 को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2025-26 [विधानसभा](#) में पेश किया।

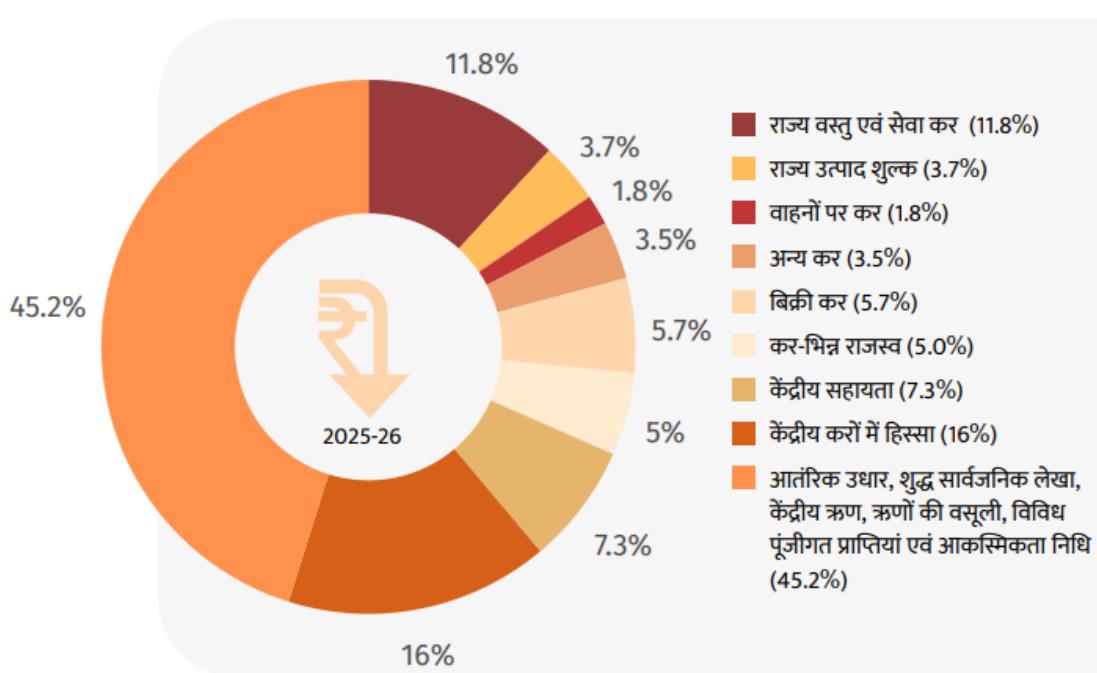
मुख्य बिंदु

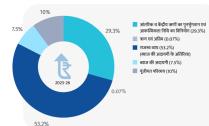
■ बजट के बारे में:

- यह पहला ग्रीन थीम आधारित बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास, [बुनियादी ढाँचे](#) और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- बजट में महलियाँ, कसिनों और युवाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं।

//

रुपया आता है





■ मुख्य घोषणाएँ:

○ पेयजल:

- आगामी वर्ष में बीस लाख घरों में कनेक्शन देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु 425 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री जल जीवन मशिन** (शहरी) की शुरुआत की गई है जिसके तहत 5830 करोड़ का प्रावधान।

○ ऊर्जा:

- आगामी वर्ष में 6400 मेगावाट से अधिक बजिली का उत्पादन करना।
- 50 हजार नए कृषि कनेक्शन और पाँच लाख घरेलू कनेक्शन देना।
- 765KV का एक, 400KV के पाँच, 220KV के 13 और 132KV के 28 और 33/11KV के 133 जीएसएस बनेंगे।
- आगामी वर्ष में नजी क्षेत्र के माध्यम से 10 ग्रामावाट बजिली का उत्पादन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री नशिलक बजिली योजना** के तहत 150 यूनिट प्रतिमाह बजिली नशिलक दी जाएगी।

○ परविहन विकास:

- सड़कों के विकास के लिये 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कारब्य किये जाएंगे।
- नौ **ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे** पर 60000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पैवबल सड़क कारब्य होंगे।
- 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में 500 करोड़ की लागत से 'अटल प्रगतिपथ' बनेंगे।
- 500 नई रोडवेज बसें जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिये 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- जयपुर मेट्रो:** 12000 करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड तक) विस्तार होगा, इसके साथ ही जगतपुरा, वैशाली नगर के लिये डीपीआर बनेंगी।
- 'पंचगौरव योजना' के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सवामतित योजना** में 2 लाख परविहारों को पटटे दिये जाएंगे।
- मनरेगा के अंतर्गत 3400 लाख मानव दिविसों का सृजन किया जाएगा।
- जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार में 250 करोड़ खर्च होगे। इसके अलावा जयपुर में बने बीआरटीएस कोरडिओर को हटाया जाएगा।
- डांग, मगरा, मेवात एवं बरजि क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- दलिली-जयपुर, जयपुर-आगरा और जयपुर-कोटा हाईवे** पर सड़क सुधार कर 'Zero Accident Zones' का नियमान।
- 20 ट्रॉमा सेंटर्स का PPP मोड में सुदृढ़ीकरण हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान।
- 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुवधा।

○ नगरीय विकास:

- पारकगि, रनिवेशन, रेजीडेंशिल फ्लैट, बस स्टैंड आदि के विस्तार एवं विकास के लिये 780 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 7 वर्षों की अवधि की पंडति दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिये 12050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार सदरीट लाइट लगाये जाएंगे।
- 500 पकि टॉयलेट्स के नियमान हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 30 नगर परिवर्तों में **Mechanised Transfer Stations** की स्थापना की जाएगी।

○ औद्योगिक विकास:

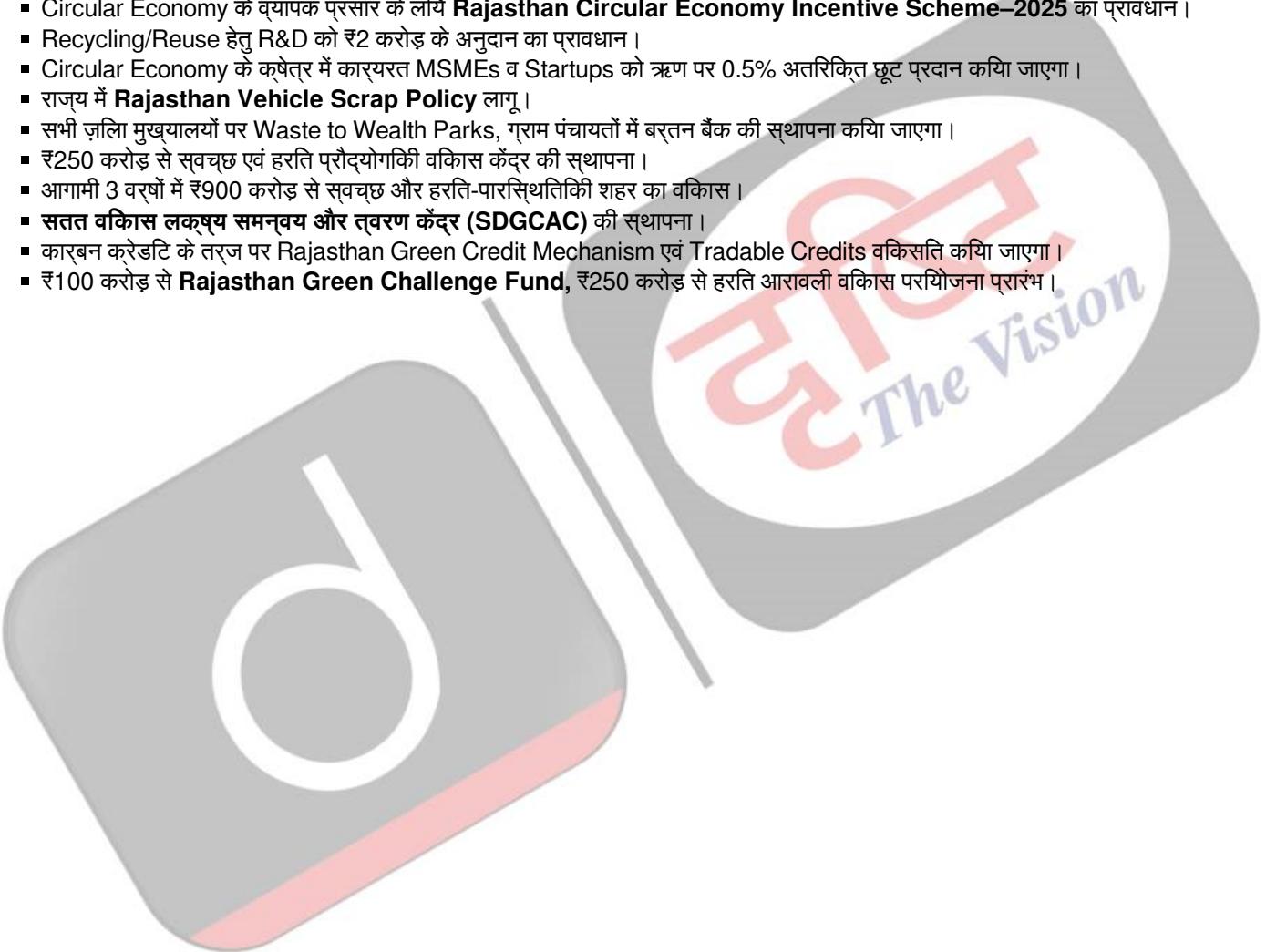
- औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 'Single Window-One Stop Shop' के माध्यम से ऑनलाइन अनुमतियों की संख्या बढ़ाकर 149 करना।
- विभिन्नों के लिये Competitive Index** लागू होगा। **Rising Rajasthan** के MoUs को प्रभावी बनाने हेतु PMU गठित किया जाएगा। Flatted Factory की व्यवस्था लागू। **Plug and Play Model** के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
- सेवा क्षेत्र में नविश के लिये **Global Capability Centre (GCC)** Policy और व्यापार संवर्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy लागू होगी।
- औद्योगिक पारकों के विकास में कोटा में टॉय पारक, नमिबाहेड़ा-चत्तिलौडगढ़ व बूंदी में स्टोन पारक, सोनयाणा-चत्तिलौडगढ़ में सेरामिक पारक, DMIC के तहत फारमा पारक, भीलवाड़ा में टेक्स्टाइल पारक का विस्तार तथा सांगनेर-जयपुर में ब्लॉक प्रटिगि जॉन स्थापति किया जाएगे।
- 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत विकास हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान। नजी औद्योगिक पारकों में CETP के लिये सहायता दी जाएगी। **DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor)** से जुड़े दो लॉजसिटिक पारक बनाए जाएंगे और PM Gati Shakti अपडेट सिस्टम विकसित किया जाएगा।

○ प्रयोग, कला एवं संस्कृति:

- पर्यटन विकास के लिये ₹975 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- जयपुर में **IIFA Awards** आयोजन। Heritage Tourism के तहत 10 Iconic Tourist Destinations विकासित किये जाएंगे, जबकि Night Tourism को बढ़ावा देने हेतु ₹100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- ऐतिहासिक कलात्मक हवेलीयों का शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं **Heritage Walk** के तहत संरक्षण कार्य किये जाएंगे। जयपुर अलबर्ट हाल मध्यूजियम के उन्नयन के लिये ₹25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- आदिवासी पर्यटन हेतु ₹100 करोड़ रुपए से Tribal Tourist Circuit विकासित होगा।
- Flying Training Organisation (FTO) प्रतापगढ़, झालावाड़ा एवं झुंझुनू में की स्थापना। जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में **Hop-on-Hop-off बस सेवा**।
- वभिन्न मंदरिंग के उन्नयन हेतु ₹101 करोड़ का प्रावधान, मंदरिंग में भोग राशि ₹3,000 प्रतिमिह और पुजारियों का मानदेय ₹7,500 प्रतिमिह किया गया।
- युवा विकास एवं कल्याण:
 - राजस्थान रोजगार नीति-2025 लाने की घोषणा।
 - 500 करोड़ का 'विकानन्द रोजगार सहायता कोष' की स्थापना होगी।
 - आगामी वर्ष में 1.25 लाख पर्यावरण भरतयां होगी। नजी क्षेत्र में लाख 1.50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
 - 'वशिष्वकरमा युवा उद्धमी प्रोत्साहन योजना' का शुभारंभ होगा। युवाओं को ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान एवं 5 लाख युवाओं को मार्जनि सहायता।
 - प्रत्येक संभाग में उन्नत कौशल और कैरियर प्रामरण केंद्र की स्थापना।
 - जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक प्रश्नान्वयन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
 - दरोणाचार्य पुरस्कार विजिता प्रशक्षिकों की भूमि आवंति की जाएगी।
 - उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर सभाग में पैरास्पोर्ट्स के लिये स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेंगे।
- चकितिसा एवं स्वास्थ्य:
 - अमजन को निःशुल्क जाँच व दवा हेतु ₹3,500 करोड़ का 'MAA कोष' का गठन। MAA योजना में Interstate Portability लागू।
 - 7 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को घर पर निःशुल्क दवा। सभी ज़लिया चकितिसालयों में Diabetic Clinics स्थापित। TB मुक्त प्रदेश हेतु CHC पर Digital X-ray, TRU-NAAT व CB-NAAT मरींगों की उपलब्धता होगी।
 - HIV संकरमति व जोखमिग्रस्त महलियों की Cervical Cancer जाँच।
 - निःशुल्क नेतर जाँच व ऑपरेशन हेतु MAA नेतर वाउचर योजना लागू।
 - 148 अरबन आयुषमान आरोग्य मंदरि (UAAM) स्थापित होंगे।
 - बीकानेर चकितिसालय में **Vitreo Retina Surgery Unit** का उन्नयन।
 - जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 120-बेड क्षमता के स्पाइनल इंजरी सेंटर की क्षमता में वृद्धि।
 - कोटा मेडिकिल कॉलेज में कैंसर यूनिट व कॉटेज वार्ड हेतु ₹195 करोड़।
 - प्रत्येक संभाग मुख्यालयों पर अलट्रा एडवांसड बर्न केयर सेंटर की स्थापना।
 - राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकिल साइंसेज (RIMS) जयपुर उन्नयन हेतु ₹500 करोड़; 750 चकितिसक व 1,500 पैरामेडिकिल पद सृजित किये जाएंगे।
 - 'Fit Rajasthan' अभियान हेतु ₹50 करोड़ प्रावधान; आहार में तेल की मात्रा 10% घटाने पर जोर।
 - नवीन आयुष नीति गाँवों को आयुषमान आरोग्य ग्राम घोषित कर ₹11 लाख प्रोत्साहन।
 - 7 ज़लियों (हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सरियाँ, चत्तीड़गढ़ एवं ढूंगरपुर) में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा:
 - सामाजिक सुरक्षा के तहत मलिने वाली पेंशन अब 1250 रुपए प्रतिमिह होगी।
 - असंगठित शर्मकियों के लिये **Gig and Unorganised Workers Fund** में ₹350 करोड़ का प्रावधान।
 - बालकियों को 35 हजार सूकूड़ी वितरण का प्रावधान।
 - प्रत्येक बलॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में 'रानी लक्ष्मीबाई केंद्र' स्थापित होगा।
 - लखपति दीदी शरणी में 20 लाख महलियों को लाने का लक्ष्य।
 - धूमंतू समुदायों के लिये 'दातूदयाल धूमंतू सशक्तिकरण योजना' शुरू।
 - अनुजा., ओबीसी व अलपस्थियक नगिम ऋणों के लिये बन टाइम स्टलमेंट योजना (OTSS)।
 - 5 हजार उचित मूल्यों की दुकानों पर 'अनन्पूरण भंडार' की स्थापना।
 - ग्रन्थवती महलियों को अतरिक्त पोषण हेतु **मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना** लागू।
- कानून व्यवस्था तथा सुशासन:
 - 'राजस्थान नागरकि सुरक्षा अधिनियम' के तहत Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ीकरण।
 - 2 वर्षों में: पुलिस को 1,000 वाहन एवं 3,500 नवीन पद सृजित।
 - **Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room** की स्थापना पर ₹350 करोड़ व्यय का प्रावधान।
 - विचाराधीन बंदियों की पेशी हेतु 400 Video Conference (VC) Nodes की स्थापना।
 - 7 केंद्रीय कारागारों में अवैध मोबाइल सार्गनल रोकने हेतु T-HCBS प्रणाली की स्थापना।
 - सजायाप्ता बंदियों के लिये न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान।
 - अजमेर कारागर प्रशक्षण संस्थान का उन्नयन।
 - अतरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय: शाहपुरा (जयपुर), रगिस (सीकर)।
 - पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय: रायपुर-बयावर, खाटूश्यामजी (सीकर)।
 - 8 नए साइबर पुलिस थाने स्थापित करने का प्रावधान।

- आगामी वर्ष में 3 हज़ार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में 'अटल ज्ञान केंद्र' स्थापित होंगे।
- अबेडकर संविधान अधिययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना।
- विभिन्नीय कार्यों के डिजिटलीकरण व पेपरलेस प्रणाली हेतु अधिकारियों-करमचारियों को टैबलेट्स हेतु ₹250 करोड़ व्यय का प्रावधान।
- ₹400 करोड़ से अधिक RajNET 2.0 प्रणाली लागू। **RajNET 2.0** से कनेक्टिविटी क्षमता में दोगुनी वृद्धि।
- आपदा रकिवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित होगा।
- ब्रह्मगुप्त पर्संटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित होगा।
- नए 8 ज़िलों में ज़ालिया स्तरीय कार्यालयों हेतु ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
- **कार्यक्रम कल्याण:**
 - सभी मानदेय करमणों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% वृद्धि।
 - NFSA डीलरों के कमीशन में 10% वृद्धि।
 - न्यायकि सेवा के पेशनरेस को 70 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त भत्ता।
 - सरकारी करमचारियों को **1 अप्रैल 2024** से बढ़ी हुई **Gratuity** का लाभ मिलेगा।
 - पत्रकार कल्याण राशि 1 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए किया गया।
 - पत्रकारों को Exposure Tour की सुविधा उपलब्ध।
- **कृषि बिज़ट:**
 - राम जल सेतु लकि परियोजना के लिये ₹9,300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
 - मनोहरथाना सचिर्वार्षि परियोजना हेतु ₹2,250 करोड़ का प्रावधान।
 - धौलपुर लफ्टिंग परियोजना एवं कालीतीर परियोजनाओं के लिये ₹950 करोड़ रुपए का प्रावधान।
 - 100 एनकिटों का नरिमाण व जीर्णोदधार हेतु ₹500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
 - **Micro Irrigation:** 1 लाख हेक्टेयर+ क्षेत्र में योजना, 3.50 लाख हेक्टेयर में Drip व Sprinkler सिस्टम हेतु ₹1,250 करोड़ व्यय का प्रावधान।
 - 25 हज़ार फारम पॉड, 10 हज़ार डिगिगियाँ, 50 हज़ार सौर पम्प व 20 हज़ार कमी पाइपलाइन हेतु ₹900 करोड़ का प्रावधान।
 - **PM कसिन समान नधि:** वार्षिक सहायता ₹9,000 किया गया।
 - गेहूं के MSP पर बोनस ₹150 प्रति किलो।
 - राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के तहत आगामी वर्ष में ₹1,350 करोड़ के कार्य प्रस्तावित।
 - 1,000 Custom Hiring Centres स्थापित किये जाएंगे।
 - आधुनिक कृषिउत्पकरणों के लिये ₹300 करोड़ का अनुदान, 1 लाख कसिनों को लाभ मिलेगा।
 - मृदा शक्ति संवर्द्धन योजना के तहत हरी खाद के लिये 3 लाख ढैंचा बीज मनीकिट उपलब्ध।
 - कृषि क्षेत्र में नवाचार हेतु AI Excellence Centre की स्थापना की जाएगी।
 - बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize व भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना की जाएगी।
 - 75 हज़ार कसिनों के लिये 30 हज़ार कमी. तारबंदी हेतु ₹324 करोड़ व्यय।
 - एक लाख भूमिहीन कृषि शरमकियों को ₹5,000 तक के कृषियंतर व उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - 100 Farmer Producer Organizations (FPOs) सदस्य कृषकों को विदेश (Israel सहित) व 5 हज़ार कृषकों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।
 - Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन होगा।
 - 35 लाख से अधिक कसिनों को ₹25,000 करोड़ के ऋण देने का प्रावधान। ₹768 करोड़ ब्याज अनुदान पर व्यय का प्रावधान।
 - Gopal Credit Card के तहत 2.50 लाख गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान।
 - दीर्घकालीन सहकारी कृषि वैगैर-कृषि क्षेत्र हेतु ₹400 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान।
 - नवीन स्थापित 8 ज़िलों में क्रय-वक्रय सहकारी संघ (KVSS) स्थापित होंगे।
 - अनूपगढ़-शरीगंगानगर में मनी फूड पार्क एवं सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क बनेंगे।
 - कृषिउत्पादों की गुणवत्ता सुधार हेतु Power Cleaning Machines।
 - बांरा में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
- **पशुपालन एवं डेयरी:**
 - मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: बीमति पशुपालकों की संख्या दोगुनी, ₹200 करोड़ अतिरिक्त व्यय का प्रावधान।
 - पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना: औषधियों व टीकों की संख्या बढ़कर 200।
 - दुग्ध उत्पाद व पशुआहार संयंतर: Milk Plants की क्षमता वृद्धि विवित सितार हेतु ₹540 करोड़।
 - नवीन दुग्ध संयंतर: अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर में, ₹225 करोड़ लागत।
 - नवीन बाईपास परोटीन पशुआहार संयंतर: राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर में ₹150 करोड़ व्यय।
 - दुग्ध संग्रहण लक्ष्य: 13 लाख लीटर, 1,000 नई सहकारी समतियों/संग्रह केंद्र स्थापित।
 - गौशालाएँ व नंदीशालाएँ: प्रति पिशु अनुदान ₹50 प्रतिदिन।
 - 200 ग्राम पंचायतों में नए पशु चकितिसा उप केंद्र स्थापित होंगे।
 - बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab स्थापित किया जाएगा।
 - 100 पशु चकितिसा अधिकारी व 1,000 पशुधन नरीकृषक नियुक्त होंगे।
- **ग्रीन बज़ट:**
 - राज्य का पहला ग्रीन बज़ट प्रस्तुत किया गया।

- 10 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस- (1) **जलवायु परविरतन** अनुकूलन (2) **बन एवं प्रयावरण-** जैव विविधता/पारसिथिकी (3) सतत कृषि, जल संचयन/पुनर्भरण (4) सतत भूमिउपयोग (5) हरति ऊर्जा (6) पुनरचक्रण एवं अपशिष्ट निपटान-परपितर अरथव्यवस्था (7) स्वच्छ तकनीक विकास (8) हरति लेखा परीक्षा (9) क्षमता नरिमाण-शक्तिशास्त्र, कौशल (10) हरति वित्त पोषण।
- 5 वर्षीय 'जलवायु अनुकूलन योजना-2030' लागू।
- ₹150 करोड़ की लागत से **Centre of Excellence for Climate Change** स्थापित होगा।
- हरति क्षेत्र वसितार हेतु **Tree Outside Forest** (ToFR) Policy व एग्रो-फॉरेस्ट्री नीति लागू।
- सवाई माधोपुर में घड़याल पालन केंद्र स्थापित होंगे।
- नेशनल नैचुरल फार्मिंग मशिन: आगामी वर्ष 2.50 लाख कसिानों को अनुदान।
- **जैविक खेती:** 1 लाख कसिानों को जैव एजेंट्स व बायोपेस्टसिइड्स का लाभ।
- **लघु एवं सीमांत कसिानों** को बैल से खेती हेतु ₹30 हजार का प्रतोत्साहन, गोबर गैस संयंत्र पर सब्सिडी।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: 4700+ गाँवों में Water Harvesting Structures पर ₹2,700 करोड़ व्यय का प्रावधान।
- **विकास राजस्थान @2047:** GIS आधारित Green Land Use Perspective Plan।
- सौर उपकरणों के बढ़ते उपयोग हेतु सोलर दीवी के रूप में नवीन मानदेय, 25 हजार महलियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- PHED (Public Health Engineering Department) के पंपणी स्टेशनों को Hybrid Annuity Model (HAM) मॉडल से सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
- Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिये **Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025** का प्रावधान।
- Recycling/Reuse हेतु R&D को ₹2 करोड़ के अनुदान का प्रावधान।
- Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs व Startups को ऋण पर 0.5% अतरिकित छूट प्रदान किया जाएगा।
- राज्य में **Rajasthan Vehicle Scrap Policy** लागू।
- सभी ज़िला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks, ग्राम पंचायतों में बरतन बैंक की स्थापना किया जाएगा।
- ₹250 करोड़ से स्वच्छ एवं हरति प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना।
- आगामी 3 वर्षों में ₹900 करोड़ से स्वच्छ और हरति-पारसिथिकी शहर का विकास।
- सतत विकास लक्ष्य समनवय और त्वरण केंद्र (SDGCAC) की स्थापना।
- कारबन क्रेडिट के तरज पर Rajasthan Green Credit Mechanism एवं Tradable Credits विकसित किया जाएगा।
- ₹100 करोड़ से **Rajasthan Green Challenge Fund**, ₹250 करोड़ से हरति आरावली विकास परियोजना प्रारंभ।



प्राप्तियां

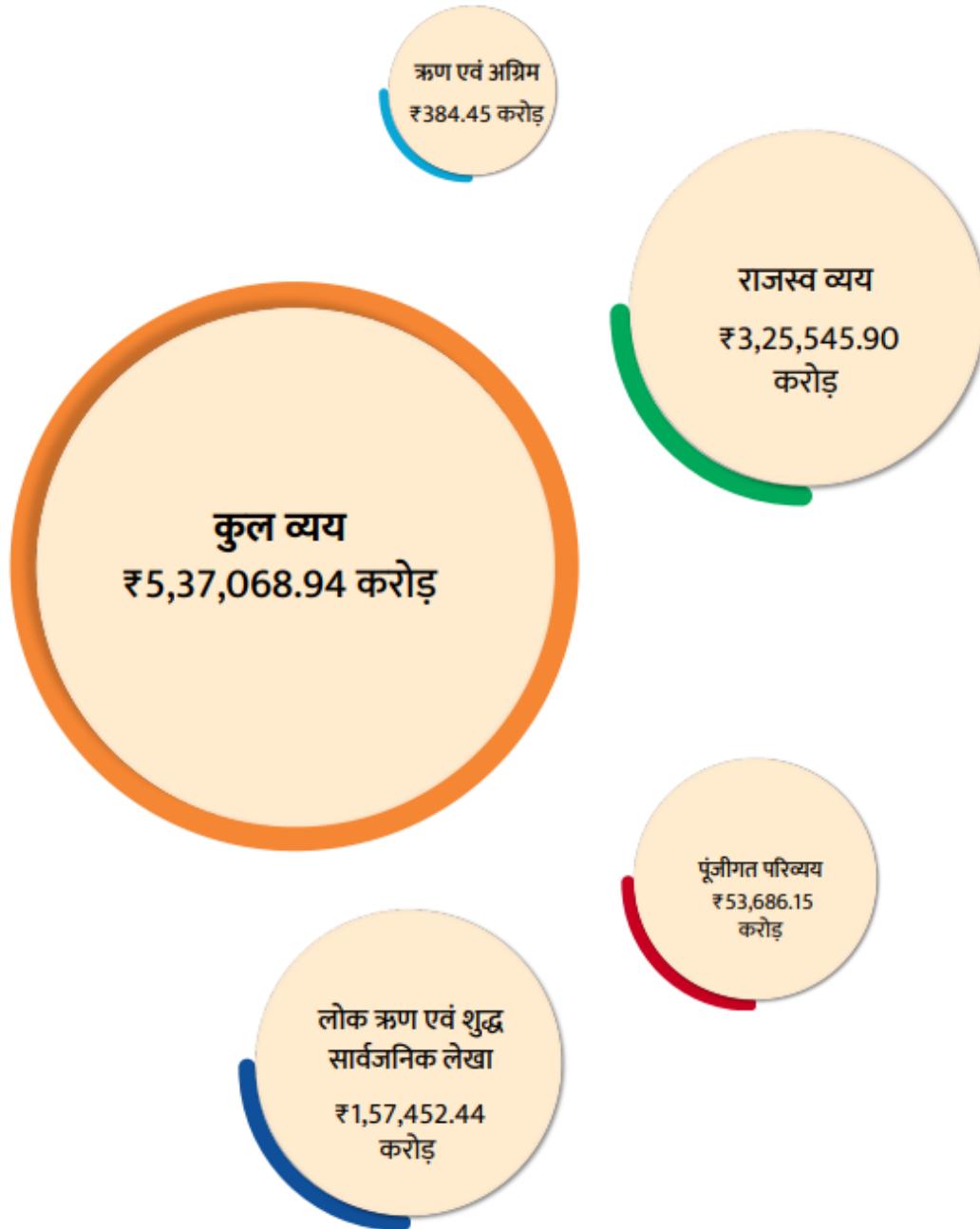
2025-26





व्यय

2025-26



विवरण	वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तार्थी	₹2,94,536.49 करोड़
राजस्व व्यय	₹3,25,545.90 करोड़
राजस्व घाटा	₹31,009.41 करोड़
राजकोषीय घाटा	₹84,643.63 करोड़ (GSDP $\frac{2}{3}$ 4.25%)
अनुमानित GSDP (वर्ष 2025-26)	₹19,89,000 करोड़ से अधिक
लक्ष्य (वर्ष 2030 तक)	\$350 बिलियन की अरथव्यवस्था नरिमाण

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-budget-2025-26>

